राज्य के किसानों की सेवा में प्रगामी कदम उठाते हुए हरियाणा सरकार ने 15 जुलाई 2010 को हरियाणा फार्मर्स कमीशन स्थापित करने का निर्णय लिया जिसे अब सामान्य रूप से 'हरियाणा किसान एवं कृषि लागत व मूल्य आयोग कहा जाता है और इसका मुख्यालय अनाज मंडी, सैक्टर–20, पंचकुला में है।

डॉ. रमेश कुमार यादव, इस आयोग के अध्यक्ष हैं। श्रीमती नवराज संधू, आई.ए.एस. अतिरिक्त प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग; डॉ. के.पी. सिंह, कुलपति, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार; डॉ. श्याम भास्कर और डॉ. राजेन्द्र सिंह बाल्यान इसके सदस्य है। वर्तमान में डॉ. राजेन्द्र सिंह बाल्यान को सदस्य–सचिव का कार्यभार दिया गया हैं।

मुख्य उद्देश्य

- हरियाणा कृषि, इसके निष्पादन, इसकी शक्तियों और निर्बलताओं की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करना।
- विभिन्न कृषि जलवायु वाले क्षेत्रों में किसानों की विभिन्न श्रेणियों की दशाओं का मूल्यांकन करना तथा राज्य में टिकाऊ और समान कृषि विकास प्राप्त करने के लिए वृहत कार्यनीतियां तैयार करना।
- खेती से होने वाली आय में आने वाली गिरावट के लिए उत्तरदायी कारकों का विश्लेषण करना और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए उपाय सुझाना।
- राज्य की प्रमुख फार्मिंग प्रणालियों की उत्पादकता, लाभप्रदता, टिकाऊपन और स्थिरता को बढ़ाने की विधियां प्रस्तावित करना।
- व्यावहारिक और सक्षम फसल (बागवानी सहित) – पशुधन, मछली समेकित प्रणाली के लिए सुझाव देना तथा कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों में सामंजस्य स्थापित करना।
- बीजों, नाशकजीवनाशियों और ऋण की प्रदानीकरण प्रणालियों की कार्यविधि के साथ–साथ निवेश उपयोग की वर्तमान दक्षता की जांच करना तथा इनमें सुधार के उपाय सुझाना।
- कृषि में जल के उपयोग की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करना और इसकी दक्षता में सुधार के उपाय सुझाना।

सरकार को प्रस्तुत की गई रिपोर्टें

कमीशन द्वारा प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों को शामिल करते हुए विभिन्न तकनीकी कार्यदल गठित किए गए हैं। इन्होंने सरकार को प्रस्तुत किए जाने के लिए अपनी रिपोर्टें भेजी हैं। ऐसी अपेक्षा है कि इन रिपोर्टों से कृषि को ऊर्जावान और लाभदायक व्यवसाय बनाने की दृष्टि से कार्यनीतिपरक योजनाएं बनाने में सहायता मिलेगी।

- हरियाणा राज्य कृषि नीति का मसौदा
- किसानों के साथ परिचर्चा के आधार पर नीतिगत मुद्दों और विकल्पों पर रिपोर्ट
- हरियाणा में कृषि अनुसंधान एवं विकास के मुद्दों और विकल्पों पर रिपोर्ट
- संरक्षण कृषि पर रिपोर्ट
- हरियाणा में प्राकृतिक संसाधन प्रबंध पर रिपोर्ट
- हरियाणा में मात्स्यिकी विकास पर रिपोर्ट
- हरियाणा में बागवानी विकास पर रिपोर्ट
- हरियाणा में सुरक्षित खेती के विकास पर रिपोर्ट
- हरियाणा में पशुपालन विकास पर रिपोर्ट
- हरियाणा में फसलों की उत्पादकता बढ़ाने पर रिपोर्ट
- हरियाणा में बारानी क्षेत्र के विकास पर रिपोर्ट
- हरियाणा में किसानों को बाजार के साथ जोड़ने पर रिपोर्ट
- हरियाणा में कटाई उपरांत प्रौद्योगिकी तथा मूल्यवर्धन पर रिपोर्ट
- हरियाणा किसान आयोग की महत्वपूर्ण सिफारिशें
- हरियाणा में मधुमक्खी पालन पर रिपोर्ट
- हरियाणा में कृषि विस्तार पर रिपोर्ट
- हरियाणा में खुम्बी की खेती को बढ़ाने पर रिपोर्ट

वर्तमान में कार्यरत कार्यदल

निम्न पांच तकनीकी कार्यदल इस समय कार्यरत हैं। ये कार्यदल किसानों, वैज्ञानिकों तथा फील्ड अधिकारियों के साथ चर्चाएं व बैठक आयोजित कर रहे हैं तथा इनकी रिपोर्ट प्रतीक्षित हैं :

- हरियाणा के परिनगरीय क्षेत्रों में कृषि पर कार्यदल
- हरियाणा में दुधारू गोपशुओं व भैंसों से संबंधित पशु पोषण पर कार्यदल
- हरियाणा में जैविक खेती का प्रवर्धन पर कार्यदल
- हरियाणा में कृषि व्यापार एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का प्रवर्धन पर कार्यदल
- हरियाणा मे पराली प्रबधंन का प्रवर्धन पर कार्यदल

कमीशन द्वारा राज्य सरकार को की गई महत्वपूर्ण सिफारिशें

- कृषि के लिए ऋण पर ब्याज की दरें 4 प्रतिशत तक कम कर दी जाएं।
- खेती के लिए ऋण प्राप्त करने पर स्टैम्प ड्यूटी हटा दी जाए।
- लगभग सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाएं।
- लगभग सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जारी किए जाएं।
- राज्य पशुधन मिशन का शुभारंभ हो गया है।
- मछली तालाबों के लिए जल की दरें बहुत कम की जाएं।
- चावल–गेहूं प्रणाली में विविधीकरण को बढ़ावा देने और चावल की खेती के अंतर्गत क्षेत्र को कम करने के लिए कदम उठाए जाएं।
- चारा बीजोत्पादन के लिए रोलिंग प्लान तैयार किया जाए।
- फलों व सब्जियों को किस्मबद्ध करने के लिए एपीएमसी अधिनियम में सुधार किया जाए।
- सब्जियों और फलों के लिए मंडी शुल्क माफ किया जाए।
- एडीओ के वेतन मान संशोधित किए जाएं।

राज्य स्तर की कार्यशालाओं/सेमिनारों का आयोजन

कमीशन ने हितधारकों की समस्याओं को जानने के लिए राज्य स्तर की निम्न कार्यशालाएं आयोजित की हैं तथा उनके कार्यवृत्त प्रकाशित किए हैं :

- किसान–प्रेरित नवोन्मेषों पर राष्ट्रीय कार्यशाला
- कृषि में विविधीकरण के माध्यम से समृद्धि
- राज्यस्तरीय मत्स्यिकी मेला
- कृषि में युवाओं के लिए अवसर
- मधुमक्खी पालन पर राज्य स्तर का सेमिनार
- हरियाणा में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए कार्यशाला
- हरियाणा में कटाई उपरांत प्रौद्योगिकी एवं मूल्यवर्धन पर कार्यशाला
- खुम्बी की खेती पर राज्यस्तरीय सेमिनार
- हरियाणा के टिकाऊ भूमि उपयोग नियोजन पर कार्यशाला
- पॉपलर की वृद्धिः बाधाएं एवं नीतिगत मुद्दे

हरियाणा की टिकाऊ भूमि उपयोग योजना

हरियाणा किसान आयोग (हरियाणा किसान एवं कृषि लागत व मूल्य आयोग) ने हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र (हरसेक), हिसार को एक परियोजना स्वीकृत की

है। हरसेक ने यह परियोजना पूरी कर ली है तथा सरकार को प्रस्तुत किए जाने के लिए अपनी रिपोर्ट हरियाणा किसान आयोग एवं कृषि लागत तथा मूल्य आयोग को सौंप दी है। हरसेक ने चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की सहायता से हरियाणा के प्रत्येक जिले के लिए भूमि उपयोग की योजना तैयार की है। इस परियोजना में हरियाणा में कृषि के विकास के लिए टिकाऊ भूमि उपयोग हेतु ब्लॉक विशिष्ट सिफारिशें सुझाई गई हैं। परियोजना द्वारा की गई सिफारिशों से कृषि एवं बागवानी विभाग को राज्य में खेती के समग्र विकास में सहायता प्राप्त हो सकती है।

किसानों, नीति नियोजकों तथा वैज्ञानिकों के साथ परिचर्चा

किसानों की समस्याओं, आवश्यकताओं तथा परिवर्तन के प्रति अनुकूल ढालने की उनकी क्षमता को समझने के लिए हरियाणा किसान आयोग एवं कृषि लागत तथा मूल्य आयोग ने अनेक परिचर्चा बैठकें/कार्यशालाएं/सेमिनार आदि आयोजित किए हैं जिनमें नीति नियोजकों, वैज्ञानिकों तथा संबंधित विभाग के अधिकारियों को आपस में चर्चा करने और अपने विचारों का आदान–प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। मुख्य सिफारिशों को सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है ताकि वे अपनी नीतियों के अनुसार किसानों व समाज के कल्याण के लिए इन्हें लागू कर सकें।

'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' तथा फसल अपशिष्ट प्रबंध पर जागरूकता अभियान

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग और 'कृषि उद्यमी कृषक विकास चैम्बर (केयूकेवीसी) के सहयोग से राज्य के प्रत्येक जिले में 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' (पीएमएफबीवाई) पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली हानियों से बचाना और इस प्रकार उनकी आमदनी स्थिर करना है। किसानों के साथ आपसी चर्चा से भी फसलों के कचरे या अपशिष्ट का प्रबंध करने में सहायता मिली है तथा सरकार की नीतियों की सफलता पर भी फीडबैक प्राप्त हुए हैं।

भावांतर भरपाई योजना

हरियाणा सरकार भावांतर भरपाई योजना नामक एक नई योजना लागू करने वाली पहली सरकार है। यह योजना हरियाणा किसान एवं कृषि लागत व मूल्य आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों पर शुरू की गई है। इसका उद्देश्य सब्जियों जैसे आलू, प्याज, टमाटर और फूलगोभी के मौलिक मूल्य की क्षतिपूर्ति करना है।

हरियाणा राज्य के विशिष्ट उत्पाद का ब्राण्डीकरण

हरियाणा क्षेत्र विशिष्ट विभिन्न कृषि जिंसों के लिए विख्यात है। किसानों को मूल्यवर्धित उत्पाद मंडियों में बेचने तथा एटेरना बेबी कॉर्न, मनौली स्वीट कॉर्न, तरावड़ी चावल, झज्जर खेड़ी अमरूद, डबवाली किन्नो आदि उत्पन्न करने हेतु किसानों को सुविधा प्रदान करने व प्रोत्साहित करने के लिए आयोग हरियाणा में विशिष्ट उपज के भौगोलिक संकेतों तथा ट्रेड मार्क को पंजीकृत करने का कार्य कर रहा है। इस कदम का उद्देश्य राज्य की उपज को लोकप्रिय बनाना और इसके साथ ही किसानों की आमदनी बढ़ाना भी है।

हरियाणा किसान एवं कृषि लागत व मूल्य आयोग

अनाज मंडी, सैक्टर–20, पंचकुला, हरियाणा
दूरभाष : 0172–2551764, फैक्स: 0172–2551864
ई–मेल: haryanakisanayog@gmail.com
वेबसाइट: www.haryanakisanayog.org
Whatsapp: 8437001764; Helpline: 8872111664

हरियाणा किसान एवं कृषि लागत व मूल्य आयोग

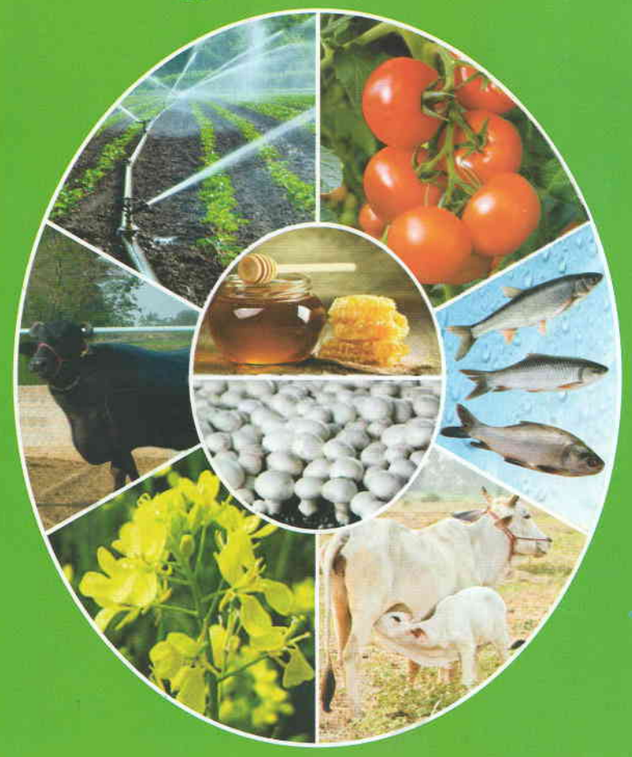

एक झलक